

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1970/भाद्र 21, 1892

No. 339] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1970/BHADRA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ORDER

New Delhi, the 12th September 1970

S.O. 3007.—The following Order made by the President is published for general information:—

Whereas by a Proclamation issued on the 4th August, 1970 under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Kerala shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas the Legislature of the State of Kerala has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1970-71;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament, expenditure of sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of one crore, sixteen lakhs, forty-seven thousand and nine hundred rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Kerala towards defraying the several charges during the financial year 1970-71 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Sl. No.	Demand No. and Services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure charges on the Consolidated Fund of the State of Kerala	Other expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Kerala	Total
1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	IV-Taxes on Vehicles	13,100	—	13,100
2.	VI-Registration fees	22,600	17,300	39,900
3.	VII-State Legislature	—	90,800	90,800
4.	VIII-Elections	—	28,41,500	28,41,500
5.	XIII-Police	41,400	6,500	47,900
6.	XVI-University Education	—	30,00,000	30,00,000
7.	XXIV-Rural Development	—	1,00,000	1,00,000
8.	XXVII-Industries	11,36,600	30,400	11,67,000
9.	XXX-Harijan Welfare	—	2,70,000	2,70,000
10.	XXXI-Statistics and Miscellaneous	—	71,600	71,600
11.	XXXII-Irrigation	—	3,86,600	3,86,600
12.	XXXIII-Public Works	—	1,87,600	1,87,600
13.	XL-Miscellaneous	13,700	3,64,500	3,78,200
14.	XLIV-Capital Outlay on Agricultural Improvement	2,07,900	—	2,07,900
15.	XLV-Capital Outlay on Industrial and Economic Development	14,45,800	—	14,45,800
16.	XLVI-Capital Outlay on Irrigation	—	1,00,000	1,00,000
17.	LV-Loans and advances by the Government	—	13,00,000	13,00,000
TOTAL		28,81,100	87,66,800	1,16,47,900

(Sd) V. V. GIRI,
President.
[No. F. 3 (4)-FCC/70]
B. MAITHREYAN, Jt. Secy:

वित्त मंत्रालय
(प्रत्यक्ष विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1970

एस० नो० 3007.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश ग्राम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन 4 अगस्त, 1970 को जारी की गयी उद्घोषणा के द्वारा यह घोषित किया गया है कि केरल राज्य

के विधान-मण्डल की शक्तियों का प्रयोग समझ द्वारा या समझ के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकेगा ;

और चूँकि केरल राज्य के विधान-मण्डल ने 1970-71 के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को प्राधिकृत किया है ,

और चूँकि कुछ सेवाओं के मामलों में इस प्रकार प्राधिकृत व्यय की रकम कम पड़ गयी है और साथ ही कुछ मामलों में ऐसे अनिवार्य व्यय की आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी कल्पना उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी ;

और चूँकि लोक सभा का मत नहीं हो रहा है और जब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने को समझ द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाता तब तक उससे व्यय किये जाने की मंजूरी देना जरूरी है ;

इसलिए, अब संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ग) के अनुसार, मैं, भारत का राष्ट्रपति, वी० वी० गिरि, एतद्द्वारा इस बात का प्राधिकार प्रदान करता हूँ कि इस आदेश के साथ लगायी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1970-71 के वित्तीय वर्ष में होने वाले अनेक प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए, केरल राज्य की समेकित निधि से, समझ की मंजूरी मिलने तक, इतनी रकमे खर्च की जाय जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित रकमों से अधिक न हों और जिनका जोड़ एक करोड़ सोलह लाख सैतालीस हजार नौ सौ रुपया हो ।

अनुसूची

क्रम मांग संख्या और सेवाएं तथा
सं० प्रयोजन

निम्नलिखित रकमों से अधिक नहीं

	केरल राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला व्यय रु०	केरल राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला अन्य व्यय रु०	जोड़ रु०
1	2	3	
1. IV-मोटर गाड़ियों पर कर .	13,100	—	13,100
2. VI-रजिस्ट्री की फीस .	22,600	17,300	39,900
3. VII-राज्य विधान मण्डल .	—	90,800	90,800
4. VIII-निर्वाचन .	—	28,41,500	28,41,500
5. XIII-गुलिस .	41,400	6,500	47,900
6. XVI-विश्वविद्यालय शिक्षा .	—	30,00,000	30,00,000
7. XXIV-ग्राम विकास .	—	1,00,000	1,00,000

1	2	3		
	XXVII—उद्योग . . .	11,36,600	30,400	11,67,000
8.	XXX—हरिजन कल्याण . . .	—	2,70,000	2,70,000
10.	XXXI—ग्रंथ संकलन और विविध . . .	—	71,600	71,600
11.	XXXII—सिचाई . . .	—	3,86,600	3,86,600
12.	XXXIII—लोक निर्माण-कार्य . . .	—	1,87,600	1,87,600
13.	XL—विविध . . .	13,700	3,64,500	3,78,200
14.	XLIV—कृषि-सुधार पर पूंजी परिव्यय . . .	2,07,900	—	2,07,900
15.	XLV—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी-परि- व्यय . . .	14,45,800	—	14,45,800
16.	XLVI—सिचाई पर पूंजी परिव्यय . . .	—	1,00,000	1,00,000
17.	LV—सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . . .	—	13,00,000	13,00,000
	जोड़ . . .	28,81,100	87,66,800	1,16,47,900

बी० बी० गिरि,
राष्ट्रपति

[मं० एफ० 3(4)—एफ० सी० सी०/70]

बी० मैन्नेयन, संयुक्त सचिव ।